राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 18747/2019

पत्तराम पुत्र मंगतु राम, आयु लगभग 36 वर्ष, गाँव और पोस्ट संघार, तहसील सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर के निवासी।---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, बीकानेर (राज.)।

3. जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, बाड़मेर (राज)।

4.प्रधानाध्यापक, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल झानपालीकलां, शिव, ब्लॉक शिव, जिला बाड़मेर।

याचिकाकर्ताओं के लिएः- श्री रामदेव राजपुरोहित।

प्रत्यर्थी (ओं) के लिएः- श्री शरवन कुमार।

मानीय न्यायाधीश श्री अरुण मोंगा

आदेश

30/01/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत दिनांक 07.12.2019 (अनुलग्नक-4) के नियुक्ति आदेश के अनुसार उसे अपने कर्तव्यों को शुरू करने की अनुमति नहीं देने की उत्तरदाताओं की कार्रवाई से उपजी है।

2. याचिकाकर्ता के दावों का सारांश देते हुए, उन्होंने शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक (पी. टी. आई.) के लिए भर्ती प्रक्रिया में विज्ञापन संख्या.09/2018 दिनांक 04.05.2018 के अनुसार भाग लिया। राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रिस्तरीय सेवा भर्ती बोर्ड, जयपुर के माध्यम से उत्तरदाताओं द्वारा विज्ञापित ग्रेड-III पद भर्ती प्रक्रिया के बाद, याचिकाकर्ता को सफल घोषित किया गया, और बाद में, 07.12.2019 को, सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, झानपालीकलां, शिव, ब्लॉक शिव, बाड़मेर में पद पर नियुक्त किया गया। हालाँकि, अपने कर्तव्यों को शुरू करने से पहले, याचिकाकर्ता के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उसके शामिल होने में देरी हुई क्योंकि प्रतिवादी संख्या 4 ने लंबित प्राथमिकी को इनकार करने के आधार के रूप में उद्धृत किया था।

3. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के साथ-साथ उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील की प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनी हैं।

4. उसी पर ध्यान देने से पहले, इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ द्वारा पारित दिनांक 19.12.2019 के अंतरिम आदेश को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जिसे पहले इस मामले को जब्त कर लिया गया था, जिसके तहत वर्तमान याचिकाकर्ता को अंतरिम संरक्षण दिया गया था, जो इस प्रकार हैः - "नोटिस जारी करें। रिट याचिका की प्रति श्री हेमंत चौधरी, जी. सी. को दी जाए, जो अगली तारीख तक मामले में अपने निर्देश/जवाब दाखिल कर सकते हैं। मामले को 14.01.2020 पर सूचीबद्ध करें। इस बीच, याचिकाकर्ता को दी गई नियुक्ति उत्तरदाताओं द्वारा रद्द नहीं की जाएगी।"

5. उपरोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए, जो कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान निर्वाह में बना हुआ है, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि विचाराधीन पद बहुत अधिक उपलब्ध है क्योंकि उस पर किसी अन्य पदधारी की नियुक्ति नहीं की गई है। हालाँकि अंतरिम आदेश के उल्लंघन के संबंध में कुछ विवाद है, जिसके लिए याचिकाकर्ता पहले ही अवमानना कार्यवाही को प्राथमिकता दे चुका है, और इसलिए, यह न्यायालय अवमानना के संबंध में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा संबोधित दलीलों पर कोई भी टिप्पणी करने से परहेज करेगा।

6. याचिकाकर्ता के मामले को उसके गुण-दोष के आधार पर देखते हुए, यह स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादियों के प्रस्तुत जवाब के अनुसार, याचिकाकर्ता ने उसके खिलाफ प्राथमिकी के संबंध में कोई जानकारी नहीं रखी थी। अपने कर्तव्यों में शामिल होने से पहले, उन्होंने स्वेच्छा से अपनी पत्नी द्वारा वैवाहिक कलह के कारण शुरू की गई आईपीसी की धारा 498-ए, 406,323,354 के तहत अनूपगढ़, जिला श्री गंगानगर के पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के

अस्तित्व का खुलासा किया। इसके अलावा, इस प्राथमिकी से उपजी आपराधिक सुनवाई याचिकाकर्ता के बरी होने के साथ समाप्त हो गई है।

7. याचिका की अनुमति नहीं देने के लिए इस स्तर पर एकमात्र विरोध अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य ने 2016 (8) एस. सी. सी. 471 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील द्वारा रखी गई निर्भरता है।

8. निर्णय पर विचार करने के बाद, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उम्मीदवारों को अपने नियोक्ताओं को दोषी ठहराए जाने, बरी किए जाने, गिरफ्तारी या लंबित आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी, नौकरी से पहले और बाद में, बिना किसी दमन या झूठे बयान के, ईमानदारी से प्रकट करनी चाहिए। नियोक्ताओं को, गलत जानकारी के कारण सेवाओं को समाप्त करते समय या उम्मीदवारी को रद्द करते समय, विशेष परिस्थितियों और प्रासंगिक सरकारी नियमों पर विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि किसी आपराधिक मामले में संलिप्तता के बारे में दमन या गलत जानकारी है, तो इसकी प्रकृति के आधार पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रमाणन/सत्यापन प्रपत्रों की सटीकता और विशिष्टता महत्वपूर्ण है, और दमन या गलत सुझाव के लिए अपराधबोध के लिए जिम्मेदार ज्ञान की आवश्यकता होती है। नियोक्ता, निस्संदेह, प्रकट की गई जानकारी पर विचार करने में अपने विवेक को बनाए रख सकते हैं और उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं हैं, भले ही सच्चे खुलासे किए गए हों, विशेष रूप से कई लंबित मामलों या गंभीर आपराधिक अपराधों से जुड़े मामलों में।

9. तत्काल मामले में याचिकाकर्ता की ओर से दमन या छिपाने का कोई आरोप नहीं है। यहां तक कि अपराध, प्रासंगिक समय पर जब वह उलझा हुआ था, किसी भी तरह से उन कर्तव्यों की प्रकृति को

प्रभावित नहीं करते थे जो याचिकाकर्ता द्वारा किए जाने थे। चाहे जो भी हो, वह किसी भी मामले में बरी हो जाता है और खुद को सही साबित कर लेता है।

10. मेरी चर्चा के परिणाम के रूप में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, याचिकाकर्ता को उस पद पर नियुक्ति से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है जिसके लिए उसे चुना गया है।

11. नतीजतन, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है, जिसमें प्रतिवादियों को इस आदेश/निर्णय की एक प्रति वेब प्रिंट के साथ याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारी को अपने आवेदन के 30 दिनों के भीतर अपने कर्तव्यों में शामिल होने की अनुमति देने के लिए अनिवार्य किया जाता है।

12. मौद्रिक लाभों के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता "कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं" के सिद्धांत का पालन करते हुए गैर-सेवा की अवधि के लिए पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा। हालांकि, उसी चयन प्रक्रिया से संबंधित अन्य सभी काल्पनिक लाभ जैसे वरिष्ठता आदि, जिसमें याचिकाकर्ता ने भाग लिया था, उसे उसी तारीख से प्रदान किया जाएगा जब उसके समकक्षों को सेवा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।